देश में पक्के गोदामों का निर्माण

*481. **श्री तारिक अनवर : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री निम्नांकित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को सुरक्षित स्थानों पर खाद्यान्नों के भंडारण हेतु पक्के गोदामों का निर्माण करने के आदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां पर निगम ने पक्के गोदामों का निर्माण इस बीच कर लिया है और किन स्थानों पर ऐसे गोदाम निर्माणाधीन हैं तथा प्रत्येक गोदाम की क्षमता कितनी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ग) वैज्ञानिक भण्डारण क्षमता का निर्माण करना भारतीय खाद्य निगम का एक अनवरत कार्यक्रम है । निगम ने 31.12.1982 तक 58.3 लाख मीटरी टन की भण्डारण क्षमता का निर्माण किया था ।

(ख) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है । **[संसद् ग्रंथालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल०टी०-6279/83]

Subletting of Accommodation Allotted to Government Employees

*482. KUMARI PUSHPA DEVI SINGH : Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of Government employees have completely sublet Government accommodation allotted to them either in General Pool or in Special Pool;

(b) whether Government have inquired into this matter in detail;

(c) if so, number of Government employees who have been found subletting Government accommodation during the last six months;

(d) whether Government propose to check ration cards, CGHS cards and other documentary proof of those staying in Government accommodation; and

(e) if not, what other measures have been adopted by Government to check such illegal subletting in Government colonies ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH) : (a) and (b) Subletting of Government Accommodation in General Pool and other pools controlled by Directorate of Estates come to notice either on the basis of complaints or through periodical surprise survey of quarters by the officers of Directorate of Estate and these are enquired into.

(c) During the period September, 1982 to Feb., 83, subletting of quarters/garages was proved against 302 employees and appropriate penalties under the rules were imposed.

(d) and (e) Documents such as Ration Card, C.G.H.S. Card and other documentary proof of persons staying in Government Accommodation are checked either while investigating subleting complaints or at the time of periodical surprise survey.

समाज के कमजोर वर्गों के लिए रिहायशी मकानों का निर्माण

*484. **श्री हरीश रावत : क्या निर्माण और आवास** मंत्री निम्नलिखित जानकारी